तीसरा मोर्चा यानि हवा में तीरंदाजी

जबर्दस्त आपसी टकरावों के बावजूद कांग्रेस की मदद से वह बीजेपी को टक्कर दे सकता है

नीरजा चौधरी

अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के तालकटोरा गार्डन में साम्प्रदायिक्ता के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा राजनैतिक पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। जैसा कि हर बार आज चुनावों से पहले होता है, तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर नेताओं ने इस संभावना से इन्कार किया। फिर भी ये लोग वहां क्यों जूटे, इसके अपने कारण हैं। लेफ्ट पार्टियों ने इसके जरिये ममता बैनर्जी से बाजी मारने की कोशिश की, जो इससे पहले नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के साथ मिलकर संघीय मोर्चे का प्रस्ताव रख चूकी हैं। इस सम्मेलन में एनसीपी के डीपी त्रिपाठी भी मौजूद थे। एनसीपी यूपीए गठबंधन का हिस्सा है लेकिन आगामी आम चुनावों में पार्टी अपने लिए विकल्प खुले रखना चाहती है। दरअसल एनसीपी दबाव की राजनीति कर रही हैं ताकि कांग्रेस को अपने लिए ज्यादा सीटें छोड़ने को कहा जा सके। 2009 में कांग्रेस ने एनसीपी के लिए 22 सीटें छोड़ी थी जबकि इस बार सिर्फ 19 सीटें देने की बात है।

अलग-अलग मकसद

सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह प्रधानमंत्री पद के सपने के साथ पहुंचे। उनक एक मकसद यूपी में अपने जनाधार में आ रही गिरावट को थामने का भी था। हालांकि वे पहले ही साफ कर चुके है कि चुनाव पूर्व तीसरे मोर्चे के गठन का कोई विचार नही है। हां, चुनाव के बाद यह उम्मीद की जा सकती है। नीतीश कुमार के लिए यह सम्मेलन नए रिश्ते बनाने का मंच था। बीजेपी से रिश्ते टूटने के बाद उन्हें नए साथियों की जरूरत है। यह दौर उनके लिए मुश्किलों भरा है। हाल ही में पटना में बम विस्फोट हुए हैं और जेल में बंद लालू यादव के प्रति संभावित सहानुभूति लहर का सामना भी उन्हें करना है। 14 गैर यूपीए और गैर एनडीए पार्टियों का एक मंच पर आना अल्पसंख्यकों के लिए एक संकेत है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती है तो नरेन्द्र मोदी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा मोर्चा 2014 में सरकार बना सकता है। इसलिए अल्पसंख्यकों को अपने-अपने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरा मोर्चा नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का व्यावहारिक विकल्प हो सकता है?

यह संभव है, बशर्ते 2014 के आम चुनावों में

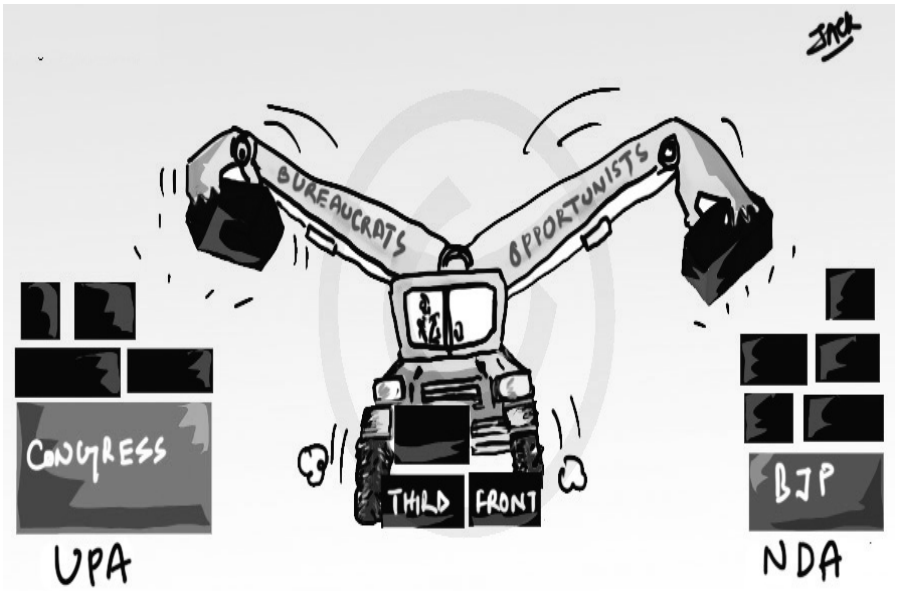

कांग्रेस जादुई आंकड़ा न छू पाए, बीजेपी को पर्याप्त सीटें ने मिलें और उसका गठबंधन विफल हो जाए। ऐसी स्थिति में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर सकती है। लेकिन एक संकट और है। गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस खेमे में कई पार्टियां ऐसी हैं एक-दूसरे की विरोधी हैं। वे एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकतीं। इस सम्मेलन में ही न मायावती पहुंची और न ममता बनर्जी। आरजेडी के नेता भी नदारद थे। क्या ऐसी स्थिति में तीसरा मोर्चा 140 सीटों का आंकड़ा छू पाएंगा? कांग्रेस (अगर उसको 100-120 सीटें मिलती है, जैसा कि तमाम सर्वेक्षणों का अनुमान है) और लेफ्ट पार्टियों (जिन्हें लगभग 35 सीटें मिल सकती है) के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने के लिए कम से कम इतनी सीटों की जरूरत होगी। क्या मुलायम या मायावती, नीतीश या लालू, जयललिता, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, टीआरएस, एससीपी और दूसरी छोटी पार्टियां मिलकर इतनी सीटें जुटा पाएंगी? इसके अलावा क्या ममता बनर्जी उस सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगी, जिसे लेफ्ट पार्टियां बाहर से समर्थन दे रही हों? क्या बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए नीतीश और लालू एक ही सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे?

तीसरे मोर्चे के मायने वैसे भी समय बीतने के साथ बदलते गए हैं। 1967 में सात राज्यों में विपक्षी दलों ने मिलकर गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई थीं। 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने सत्ता संभाली थी। 1989 में वीपी सिंह के नेशनल फंट ने भी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, जिसे लेफ्ट और बीजेपी, दोनो का बाहरी समर्थन प्राप्त था लेकिन हर बार राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं ने गैर कांग्रेसी सरकारों को नाकामयाब किया। आपातकाल के बाद जनता सरकार के गिरने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पार्टी के तीन बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह के मिजाज नहीं मिलते थे। 1989 में वीपी सिंह की सरकार को भी देवीलाल, चंद्रशेखर और बीजेपी का विरोध झेलना पड़ा था।

कांग्रेस का साथ

आज भी स्थिति कमोबेश यही है। हर नेता की अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, शरद पवार, जयललिता, यहा तक कि नवीन पटनायक की भी। सभी की दावेदारी भी मजबूत हैं। 16वीं लोकसभा का गणित ही तय करेगा कि तीसरे मोर्चे का गठन होता है या नही। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा मोर्चा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से टक्कर ले सकता है, लेकिन कांग्रेस की मदद से। हा, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाए, इसकी संभावना कम दिखती है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक चिंतक है